पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

प्रदेश में हर वर्ष आने वाली बाढ़ के लिये केन्द्र सरकार की उदासीनता जिम्मेदार–मुख्यमंत्री

बाढ़ से बचाव तथा राहत कार्यों के लिये धन की कमी नहीं होने दी जायेगी–मायावती

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की जनता को तत्परता से राहत उपलब्ध कराने के लिये सभी जरूरी कदम उठाये गये हैं

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे की समस्या के स्थायी समाधान के लिये बरसात के मौसम के दौरान 10 करोड़ पौधे लगाने का निर्णय

लखनऊ : दिनांक 01 जुलाई, 2008

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से बचाव तथा राहत कार्यों के लिये धन की कमी नहीं होने दी जायेगी। उन्होंने केन्द्र सरकार की उदासीनता को प्रदेश में हर साल बाढ़ से होने वाली तबाही के लिये जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने यह भी बताया कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे की समस्या के स्थायी समाधान के लिये इस क्षेत्र में वन महोत्सव सप्ताह के दौरान व बरसात के मौसम में 10 करोड़ पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री आज यहां अपने शासकीय आवास 5, कालिदास मार्ग पर मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हर साल प्रदेश के कुछ जनपदों, विशेष रूप से तराई एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में बाढ़ से हजारों एकड़ फसल तथा अनेक गांव प्रभावित होते हैं और साथ ही जन–धन की भी काफी हानि होती है।

सुश्री मायावती ने बताया कि उनके निर्देश पर मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में की जा रही तैयारियों की समीक्षा जून के प्रथम सप्ताह में ही कर ली गयी थी और इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिये थे। इसके अलावा सिंचाई मंत्री को भी हर सम्भावित स्थिति से निपटने के लिए सभी सम्भव उपाय करने के निर्देश दिये गये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ की गम्भीर स्थिति का एक मुख्य कारण यह भी है कि प्रदेश से होकर बहने वाली अधिकांश बड़ी नदियां, जैसे–शारदा, घाघरा, राप्ती एवं गण्डक पड़ोसी देश नेपाल से निकलती हैं और अक्सर नेपाल में अतिवृष्टि होने के कारण अथवा वहां के जलाशयों से अचानक अत्याधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के कई जनपदों में बाढ़ की विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

सुश्री मायावती ने कहा कि इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव ने विगत 21 जून को गोरखपुर, कुशीनगर और महराजगंज जनपदों का दौरा कर बाढ़ सुरक्षा प्रबंधों तथा राहत एवं बचाव कार्यों की समुचित समीक्षा की थी और इसके बाद विगत 27 जून को सिंचाई मंत्री ने भी राज्य के पूर्वांचल एवं गोरखपुर के उन क्षेत्रों का दौरा किया था, जहां बाढ़ आई है अथवा आने की सम्भावना रहती है। उन्होंने कहा कि सिंचाई मंत्री द्वारा अपने दौरे के अवसर पर मौके पर मुआयने के बाद बाढ़ सुरक्षा कार्यों में ढिलाई बरतने पर कुछ अधिकारियों को निलम्बित भी किया गया था तथा कुछ अन्य के खिलाफ विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की जनता को हर तरह की राहत तत्परता से उपलब्ध कराने के लिये उनकी सरकार द्वारा जरूरी कदम उठाये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि पी0ए0सी0 की फ्लड कम्पनी को मोटर बोट सहित अन्य सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा इसके अलावा सेना को भी सचेत कर दिया गया है और शासन के अधिकारीगण सेना के अधिकारियों से लगातार सम्पर्क में हैं।

केन्द्र सरकार की उदासीनता को प्रदेश में हर वर्ष होने वाली बाढ़ की विभीषिका के लिये जिम्मेदार ठहराते हुये सुश्री मायावती ने कहा कि शारदा, घाघरा, राप्ती एवं गण्डक नदियों में बाढ़ के चलते प्रदेश में हर साल जो तबाही होती है, उसे रोका जा सकता था, यदि केन्द्र की सरकार इस मामले को लेकर गम्भीर होती। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले साल केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि उत्तर प्रदेश में नेपाल से आने वाली नदियों से बाढ़ की समस्या से स्थायी समाधान के लिये जरूरी है कि नेपाल एवं भारत के मध्य सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी लम्बित परियोजनाओं के बारे में शीघ्र निर्णय लेकर कार्यवाही की जाये। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सरकार द्वारा अन्य अनेक मुद्दों पर किये गये अनुरोध की तरह इस मुद्दे पर भी अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसके चलते पुनः इस वर्ष स्थिति पहले जैसी ही बनी हुई है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह शुरू हो चुका है और इस अवसर का उपयोग बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे की समस्या के स्थायी समाधान के लिये करने के उद्देश्य से बागवानी पर विशेष जोर देने का निर्णय लेते हुए उनकी सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड के जनपदों में बरसात के मौसम में 10 करोड़ पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें विशेषकर नीबू प्रजाति के पौधे एवं अन्य उपयुक्त फलदार पेड़ शामिल होंगे, ताकि इस क्षेत्र के निवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि पर्यावरण संरक्षण के नजरिये से नीम, बेल, इमली आदि की प्रजातियों के वृक्ष भी लगाये जायेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद फिर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार पौधे लगाये जायेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी सरकार के इन प्रयासों से आने वाले वर्षों में प्रदेश के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा।